दैनिक

न्याय साक्षी

अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शुक्रवार 01 अक्टूबर 2021 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-04, अंक- 06

प्रधानमंत्री ने पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान का किया उद्घाटन

नई दिल्ली (आरएनएस)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिपेट (सीआईपीईटी)= पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर का उद्घाटन किया। उन्होंने राजस्थान के बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में चार नए मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने 4 नए मेडिकल कॉलेज और सिपेट (सीआईपीईटी) संस्थान के लिए राजस्थान के लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि 2014 के बाद केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 23 मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं और इनमें से 7 मेडिकल कॉलेज पहले ही शुरू हो चुके हैं।

सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 100 वर्षों की सबसे बड़ी महामारी ने दुनिया के स्वास्थ्य क्षेत्र को एक सबक सिखाया है। प्रत्येक देश अपने-अपने तरीके से इस संकट से निपटने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इस आपदा में अपनी ताकत व आत्मनिर्भरता बढ़ाने का संकल्प लिया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि राज्य का एक विषय है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने देश के हेल्थ सेक्टर की कमियों का अनुभव किया था और प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने उनको दूर करने की निरंतर कोशिश की है। उन्होंने कहा, ''देश के स्वास्थ्य सेक्टर को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमने एक राष्ट्रीय अप्रोच, एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर काम किया। स्वच्छ भारत अभियान से लेकर आयुष्मान भारत और अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन तक, ऐसे अनेक प्रयास इसी अप्रोच का हिस्सा हैं।उन्होंनेकहाकिराजस्थान में करीब साढ़े तीन लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज मिला और राज्य में करीब ढाई हजार स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्रों पर काम शुरू हुआ है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल हों, इनका नेटवर्क देश के कोने-कोने तक तेज़ी से फैलाना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने कहा, ''आज हम संतोष के साथ कह सकते हैं कि 6 एम्स से आगे बढ़कर आज भारत 22 से ज्यादा एम्स के सशक्त नेटवर्क की तरफ बढ़ रहा है।''

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले इन 6-7 सालों में 170 से अधिक नए मेडिकल कॉलेज तैयार हो चुके हैं और 100 से ज्यादा नए मेडिकल कॉलेज पर काम तेज़ी से चल रहा है। साल 2014 में देश में मेडिकल की अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट की कुल सीटें 82 हजार के करीब थीं। आज इनकी संख्या बढ़कर 1लाख 40हजार सीट तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नियमन और शासन के क्षेत्र में भी, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के आगमन के साथ, अतीत की समस्याओं और प्रश्नों का समाधान किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी स्किल्ड मैनपावर का सीधा असर प्रभावी स्वास्थ्य सेवाओं पर होता है। देश ने इस कोरोना काल में इसे और ज्यादा महसूस किया है। केंद्र सरकार के सबको वैक्सीन-मुफ्त वैक्सीन अभियान की सफलता इसी का प्रतिबिंब है। आज भारत में कोरोना वैक्सीन की 88 करोड़ से अधिक डोज लग चुकी है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में उच्च स्तर का कौशल, न सिर्फ भारत की ताकत बढ़ाएगा बल्कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने में भी बड़ी भूमिका निभाएगा। सबसे तेजी से विकसित हो रहे उद्योगों में से एक, पेट्रोरसायन इंडस्ट्री के लिए, स्किल्ड मैनपावर, आज की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि नया पेट्रोरसायन प्रौद्योगिकी संस्थान लाखों युवाओं को नई संभावनाओं से जोड़ेगा। प्रधानमंत्री ने अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल को याद किया और राज्य में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय, जो अब ऊर्जा विश्वविद्यालय है, की स्थापना और उसे प्रोत्साहन देने से जुड़े अपने प्रयासों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस तरह का संस्थान युवाओं के लिए स्वच्छ ऊर्जा नवाचारों में योगदान करने का मार्ग प्रशस्त करेगा।

प्रधानमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बाड़मेर में राजस्थान रिफाइनरी परियोजना 70,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के साथ तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य में सिटी गैस वितरण की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि 2014 तक राज्य में केवल एक ही शहर में सिटी गैस वितरण की अनुमति थी, अब राज्य के 17 जिलों को सिटी गैस वितरण नेटवर्क के लिए मंजूरी दे दी गयी है। आने वाले वर्षों में राज्य के हर जिले में पाइप वाले गैस का नेटवर्क होगा। उन्होंने शौचालय, बिजली, गैस कनेक्शन जैसी सुविधाओं के आने से शुरू हुई जीवन की सुगमता की ओर भी इशारा किया। उन्होंने कहा कि आज राज्य में जल जीवन मिशन के माध्यम से 21 लाख से अधिक परिवारों को पाइप से पानी मिल रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान का विकास, भारत के विकास को गति देता है और राज्य में गरीब परिवारों के लिए 13 लाख से अधिक पक्के घर बनाए गए हैं।

महत्वपूर्ण एवं खास

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिकीय भर्ती परीक्षाओं का आयोजन

नई दिल्ली (आरएनएस)। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सिफारिश की है कि 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए लिपिकीय भर्तियों और अब से विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ में, प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाएं, हिंदी और अंग्रेजी सहित 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित की जाएंगी। यह निर्णय सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में लिपिक संवर्ग के लिए परीक्षा आयोजित करने के मामले पर विचार करने के लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति की सिफारिश पर आधारित है। आईबीपीएस द्वारा शुरू की गई परीक्षा आयोजित करने की मौजूदा प्रक्रिया को समिति की सिफारिशें उपलब्ध कराए जाने तक रोक कर रखा गया था।

एनटीपीसी-आरईएल ने पहले हरित साविधि ऋण समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली (आरएनएस)। नेशनल थर्मल पॉवर कार्पोरेशन-नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड (आरईएल), एनटीपीसी की शत प्रतिशत सहायक कंपनी है। आरईएल ने पहले हरित साविधि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह ऋण समझौता 500 करोड़ रुपये का है जो प्रतिस्पर्धी ब्याज दर पर हासिल हुआ है। ऋण की अवधि 15 वर्ष है। उल्लेखनीय है कि आरईएल ने 29 सितंबर, 2021 को बैंक ऑफ इंडिया के साथ राजस्थान स्थित अपनी 470 मेगावॉट सौर परियोजना और गुजरात स्थित 200 मेगावॉट सौर परियोजना के लिये यह समझौता किया है। एनटीपीसी-आरईएल के पास इस समय 3,450 मेगावॉट की नवीकरणीय परियोजनायें हैं, जिनमें से 820 मेगावॉट की परियोजनायें निर्माणाधीन हैं और 2,630 मेगावॉट की परियोजनाओं को मंजूरी मिल गई है। इन परियोजनाओं के लिये बिजली खरीद समझौते (पीपीए) अभी लम्बित हैं।

मेघालय में बस दुर्घटना में चार की मौत, 16 घायल

शिलांग (आरएनएस)। मेघालय में एक बस के नदी में गिरने से कम से कम चार लोगों की मौत हो गयी और अन्य 16 घायल हो गए। यह बस वेस्ट गारो हिल्स जिला मुख्यालय के तुरा से राजधानी शिलांग की ओर जा रही थी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार , बस चालक के नियंत्रण खो देने की वजह से यह दुर्घटना घटी। उन्होंने बताया कि बस के अंदर फंसे लोगों को बाहर निकालने के लिए बचाव अभियान चला गया है। उन्होंने कहा कि यह दुघर्टना बीती देर रात हुई, जब बस पुल से फिसलकर ईस्ट गारो हिल्स और वेस्ट खासी हिल्स जिले की सीमा से सटे नोगंश्रम की रिंगड़ी नदी में जा गिरी। संगमा ने कहा, हमें अभी यह पता नहीं चला है कि बस के अंदर कितने यात्री मौजूद हैं। फंसे हुए लोगों को बचाने के प्रयास जारी है। उन्होंने कहा कि घायल यात्रियों को रोंग्जेंग पीएससी और विलियमनगर सिविल अस्पताल में में भर्ती कराया गया है।

अमेजन ने पेश किया नया होम रोबोट एस्ट्रो

सैन फ्रांसिस्को। अमेजन ने अपने लंबे समय से चर्चित होम रोबोट होम असिस्टेंट रोबोट की घोषणा की है, जिसका नाम एस्ट्रो है। रोबोट वीडियो कॉल को संभाल सकता है, उपयोगकर्ताओं को पहचान सकता है और जब कोई कॉल करता है तो उन्हें ढूंढ सकता है, और पहियों पर एलेक्सा की सभी सुविधाएं प्रदान करता है। एस्ट्रो की कीमत 1,449.99 डॉलर होगी, लेकिन पहले दिन के संस्करण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, यह रिंग प्रोटेक्ट प्रो सदस्यता के छह महीने के परीक्षण के साथ 999.99 डॉलर की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध होगा। यह सीमित मात्रा में उपलब्ध होगा, और अमेजन इस साल के अंत में अमेरिका में ग्राहकों को निमंत्रण और शिपिंग डिवाइस देना शुरू करने की योजना बना रहा है। कंपनी ने एक बयान में कहा, हमने एस्ट्रो को डिवाइस पर बहुत सारे डेटा प्रोसेसिंग को संभालने के लिए डिजाइन किया है, जिसमें छवियों और कच्चे सेंसर डेटा शामिल हैं जो इसे आपके घर के चारों ओर ले जाते हैं। इससे एस्ट्रो को अपने पर्यावरण पर त्वरित प्रतिक्रिया देने में मदद मिलती है।

महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी बलबीर गिरि बाघंबरी होंगे

हरिद्वार (आरएनएस)। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि के उत्तराधिकारी के रूप में बलबीर गिरि बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे। निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने हरिद्वार में इसकी औपचारिक घोषणा की।

निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी ने गुरुवार को हरिद्वार में इसकी औपचारिक घोषणा की। पत्रकार वार्ता में महंत रविंद्रपुरी ने बताया कि निरंजनी अखाड़े में बाघंबरी मठ में संचालन के लिए बोर्ड बनाया जा रहा है। अखाड़े के हित और मर्यादा में कार्य करवाने के लिए उक्त बोर्ड बनाया जा रहा है। जिसमें पांच लोग शामिल होंगे। षोडशी भंडारे से पहले बोर्ड का गठन होगा। बताया कि गुरुवार को निरंजनी अखाड़े में अखाड़े के पंचों की बैठक में यह निर्णय लिया गया

सीबीआई टीम प्रयागराज रवाना- वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमहंत नरेंद्र गिरि की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए हरिद्वार पहुंची सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (सीबीआई) की टीम गुरुवार को आनंद गिरि को लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई। इससे पहले सीबीआई ने आंनद गिरि से करीब साढ़े सात घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद सीबीआई की टीम आनंद गिरि को लेकर हरिद्वार से प्रयागराज के लिए रवाना हो गई।

सिद्धू और चन्नी के बीच बातचीत के बाद सुलझा विवाद

चंडीगढ़ (आरएनएस)। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की बातचीत खत्म हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सारे मामले सुलझ गए हैं। बैठक में नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बारे में बातचीत हुई। बताया जाता है कि सिद्धू पंजाब के कार्यवाहक डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता और एजी अमरप्रीत सिंह देयोल को हटाने पर अड़े हुए थे। दूसरी ओर, कांग्रेस सूत्रों ने संकेत दिया है कि दोनो की बैठक में मामला सुलझ सकता है। दूसरी ओर, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने राज्य कैबिनेट की 4 अक्टूबर को बैठक बुलाई है।

सिद्धू को दो अफसरों कार्यवाहक डीजीपी इकबाल प्रीत सिंह सहोता और एडवोकेट जनरल (एजी) अमरप्रीत सिंह देयोल की नियुक्ति पर आपत्ति है। इनकी जगह वह अपने चहेते अधिकारियों की नियुक्ति करवाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री चन्नी ने कल संकेत दिया था कि वह कुछ फैसले वापस ले सकते हैं। दूसरी ओर दबाव बढ़ाने के लिए सिद्धू ने वार्ता से ठीक पहले अपने तीखे तेवर दिखाए। उन्होंने दिनकर गुप्ता

के छुट्टी पर जाने के बाद कार्यवाहक डीजीपी बनाए गए इकबाल प्रीत सिंह सहोता पर निशाना साधा। माना जा रहा है कि इस बैठक में यह तय हो जाएगा कि सिद्धू पार्टी अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा वापस लेते हैं या नहीं। पार्टी हाईकमान ने सिद्धू के इस्तीफे के मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री चन्नी को सौंपी है।नवजोत सिंह सिद्धू ने चन्नी के साथ बैठक से पहले डीजीपी बनाए गए इकबाल प्रीत सहोता पर ट्वीट कर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि डीजीपी आइपीएस सहोता बादल सरकार के समय हुई बेअदबी की घटना की जांच के लिए गठित एसआइटी के प्रमुख थे। उन्होंने दो सिख युवकों को गलत ढ़ंग से फंसाया था और बादलों को क्लीनचिट दे दी थी। उस समय मैं कांग्रेस के कई मंत्रियों और आज के गृहमंत्री के साथ वहां गए थे और उन लोगों (फंसाए गए युवकों) के समर्थन में लड़ाई का भरोसा दिलाया था।

पाकिस्तान में होने वाले आतंकवाद विरोधी अभ्यास में हिस्सा लेगा भारत, अगले हफ्ते जाएगा 3 सदस्यीय दल

नई दिल्ली (आरएनएस)। पाकिस्तान में तीन अक्तूबर से होने वाले शंघाई सहयोग संगठन के आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भारत भी भाग लेगा। इस अभ्यास में भाग लेने के लिए भारत की और से तीन सदस्यीय टीम पाकिस्तान जाएगी। इसका उद्देश्य है कि एससीओ सदस्य देशों के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़े। सरकार का मानना है कि इस एक्सरसाइज में भागीदारी से किसी भी तरह से उसके दावे को कमजोर नहीं करेगा कि पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देता है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अगले हफ्ते पाकिस्तान में होने वाले शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने के लिए 3 सदस्यीय भारतीय टीम जाएगी। इस एक्सरसाइज में भारत की मौजूदगी को सुरक्षा से संबंधित मुद्दों, खासकर अफगानिस्तान में मध्य एशिया केंद्रित क्षेत्रीय ब्लॉक की भूमिका के महत्व के संकेत के रूप में देखा जाएगा। रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान और 4 मध्य एशियाई देशों के सदस्यों के साथ ईरान के भी स्ह्ह में आने से एससीओ के अफगानिस्तान में स्थिति के राजनीतिक और राजनयिक समाधान के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की संभावना है। भारत इस अभ्यास में अपनी भागीदारी की पुष्टि करने वाला अंतिम देश था।

ताशकंद में आरएटीएस की बैठक के बाद इस साल मार्च में इस एक्सरसाइज का ऐलान हुआ था। एससीओ प्रोटोकॉल के तहत पाकिस्तान ने भारत सहित सभी सदस्य-देशों को इस अभ्यास के लिए आमंत्रित किया था। इस एक्सरसाइज में सैनिक शामिल नहीं हैं और इसका उद्देश्य आतंकवादी गतिविधियों को फंडिंग पहुंचाने वाले चैनलों की पहचान करना और उन्हें रोकना है। इस एक्सरसाइज में भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के अधिकारियों के करने की संभावना है।

एससीओ एक्सरसाइज ऐसे समय में होगा जब इस साल फरवरी में दोनों पक्षों के बीच युद्धविराम समझौते पर पहुंचने के बावजूद भारत-पाकिस्तान संबंध खराब से बदतर होते जा रहे हैं। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी कमांडरों पर पिछले महीने जम्मू-कश्मीर में घुसपैठ कराने का आरोप लगाया है और इस हफ्ते की शुरुआत में सेना ने नियंत्रण रेखा के उरी सेक्टर में एक मुठभेड़ के बाद एक पाकिस्तानी आतंकवादी को हिरासत में लिया था। अफगानिस्तान पर एससीओ समिट की मीटिंग को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि तालिबान द्वारा बनाई गई सरकार समावेशी नहीं थी और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से इसे पहचानने में जल्दबाजी न करने को कहा। घोषणापत्र में अफगानिस्तान को आतंकवाद और नशीले पदार्थों से मुक्त करने का आह्वान करते हुए कहा गया कि सभी सदस्य देशों का मानना है कि अफगानिस्तान में एक समावेशी सरकार का होना जरूरी है, जिसमें अफगान समाज के सभी जातीय, धार्मिक और राजनीतिक समूहों के प्रतिनिधि हों।

असम ने 2 बंद पेपर मिलों के कर्मियों के लिए 570 करोड़ रुपये के पैकेज की घोषणा की

गुवाहाटी (आरएनएस)। असम सरकार ने सरकार द्वारा संचालित हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के स्वामित्व वाली दो पेपर मिलों के कर्मचारियों और कर्मचारियों के साथ 56 महीने से लंबित उनके वेतन और बकाया के मुद्दों को हल करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों के लिए 570 करोड़ रुपये के राहत पैकेज के लिए मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के कार्यालय में चार घंटे से अधिक की मैराथन चर्चा के बाद सरकार और दो पेपर मिलों की यूनियनों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। बहुप्रतीक्षित सौदे के बाद, सरमा ने ट्वीट किया, आखिरकार हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों और कर्मचारियों के साथ उनके वेतन और बकाया के लंबे समय से लंबित मुद्दों को हल करने के लिए समझौता किया। हैलाकांडी जिले में एचपीसीएल के कछार पेपर मिल (सीपीएम) में उत्पादन 20 अक्टूबर, 2015 को बंद हो गया, जबकि मोरीगांव के जगीरोड में नौगांव पेपर मिल (एनपीएम) 13 मार्च, 2017 से बंद है। दोनों मिलों के 2,500 से अधिक कर्मचारियों को चार साल से अधिक समय से वेतन नहीं मिला है।

11,000 से अधिक भंडार धारकों ने केंद्र के पोर्टल पर दालों का भंडार घोषित किया

नई दिल्ली (आरएनएस)। उपभोक्ता मामले विभाग के आधिकारिक पोर्टल पर 20 सितंबर, 2021 तक कम से कम 11,635 भंडार धारकों ने 3097694.42 मीट्रिक टन दालों के भंडार की घोषणा करते हुए पंजीकरण कराया है।

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का उपभोक्ता मामले विभाग 22 आवश्यक खाद्य वस्तुओं के खुदरा और थोक मूल्यों की निगरानी कर रहा है। यह विभाग द्वारा विभिन्न प्रभावी नीतिगत उपायों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है जैसे कालाबाजारी पर अंकुश लगाना, निर्यात को प्रतिबंधित करके उपलब्धता बढ़ाना और आयात को

प्रोत्साहित करना, बफर स्टॉक बनाना एवं असामान्य मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए समय पर भंडार जारी किया जाना सुनिश्चित करना।

इस सिलसिले में खुले बाजार में उपलब्ध दालों के आंकड़ों का दोहन करना जरूरी था। इसलिए, माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल की मंजूरी के साथविभाग ने स्टॉकिस्ट, मिल मालिकों, आयातकों और डीलरों जैसे विभिन्न भंडार धारकों को किसी भी दी गयी तारीख पर अपने पास मौजूदभंडारकी जानकारी देने की खातिर प्रोत्साहित करने के लिए एक पोर्टल तैयार किया है।

व्यापारियों, मिल मालिकों, आयातकों, और सरकारी एवं निजी स्वामित्व वाले गोदामों के माध्यम से भंडार की घोषणा की मदद से एक डेटा बैंक बनाया जाएगा। इससे सरकार को यह समझने में मदद मिलेगी कि वे कौन से राज्य हैं जो कटाई-पिसाई-पेराई (मिलिंग) आदि उद्देश्यों के लिए उत्पादन और भंडारण करते हैं। भंडार संबंधी इस घोषणा और उस के रियल-टाइम सत्यापन के माध्यम से जमाखोरी और कृत्रिम कमी पैदा करने की अवांछनीय प्रथाओं पर रोक लगाने में भी मदद मिलेगी।

पोर्टल - https://fcainfoweb.nic.in/psp - को भी कोई भी नागरिक एक्सेस कर सकता है। ओटीपी के माध्यम से ईमेल और मोबाइल के सत्यापन के बाद हितधारक पोर्टल में पंजीकरण कर सकते हैं और यूजर आईडी एवं पासवर्ड बना सकते हैं। यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के बाद, वे अपने विवरण एवं भौगोलिक जानकारी जोड़कर अपने प्रोफाइल में जानकारी साझा करते हैं और किसी भी तारीख को अपने भंडार में मौजूद अलग-अलग दालों की जानकारी देते हैं। जब भी भंडार में कोई वृद्धि या घटाव होता है, तो डेटा को अपडेट करना हितधारकों की जिम्मेदारी है।

डेटा की गोपनीयता बनाए रखी जाती है। राज्य और केंद्र सरकार के अलावा किसी भी भंडार धारक द्वारा घोषित डेटा उन्हें दिखाई देगा। डेटा उन्हें किसी भी तारीख को भंडारों की आवाजाही और उनके साथ भंडार की मात्रा जानने में मदद करता है। राज्य सरकारें अपने स्वयं के राज्यों से संबंधित विभिन्न हितधारकों द्वारा किए गए पंजीकरण और घोषित भंडार की निगरानी कर सकती हैं। यह उनके राज्य में उपलब्ध विभिन्न दालों के भंडार की मात्रा का डेटा देता है। यह किसी विशेष दाल की उपलब्धता में किसी भी अपेक्षित कमी के बारे में भी जानकारी देता है ताकि राज्य सरकार स्थिति के